भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **182**
गुरुवार, 02 फरवरी, 2023/ 13 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ईंधन लागत बनाम प्रचालन लागत

182. श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रचालन प्रभारों के प्रतिशत के रूप में ईंधन लागत 30 प्रतिशत के वैश्विक औसत की तुलना में 45 प्रतिशत है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ईंधन की खपत को प्रभावित किए बिना इसकी कीमत/कम/नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(ग) क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र की लेन-देन लागत में केन्द्रीय और राज्य करों को कम करने की कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) एयरलाइनों की परिचालन लागत गतिशील होती है और उनकी विशिष्ठ स्थितियाँ कई कारकों के आधार पर भिन्न होते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमत, विदेशी विनिमय दरें, शुल्क और कर आदि शामिल हैं। अनुसूचित भारतीय प्रचालकों के मामले में, विमान ईंधन और तेल व्यय का प्रतिशत हिस्सा कुल परिचालन व्यय का लगभग 40% रहा है।

(ख) और (ग) एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतें 01.04.2001 से सरकार ने बाजार द्वारा निर्धारित बना दी हैं। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद कीमतों और अन्य बाजार स्थितियों के अनुरूप एटीएफ के मूल्य पर उचित निर्णय लेती हैं। सरकार एटीएफ कीमतों के मामले पर एयरलाइनों और ओएमसी के साथ निरंतर विचार –विमर्श करती रही है। राज्यों द्वारा एटीएफ पर लगाए गए उच्च मूल्य वर्धित कर (वीएटी) का संज्ञान लेते हुए, इस मुद्दे को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ उठाया गया था। परिणामस्वरूप, 17 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा एटीएफ पर वीएटी को घटाया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

I) राज्य जिन्होंने एटीएफ पर वीएटी को 1-4% स्तर तक कम किया है:

i. अंडमान और निकोबार द्वीप
ii. उत्तराखंड

iii. जम्मू और कश्मीर
iv. लद्दाख
v. हिमाचल प्रदेश
vi. त्रिपुरा
vii. मध्यप्रदेश
viii. हरियाणा
ix. उत्तरप्रदेश
x. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
xi. अरुणाचल प्रदेश
xii. मणिपुर
xiii. झारखंड
xiv. मिजोरम

II) अन्य राज्य जिन्होंने एटीएफ पर वीएटी को घटाया है:

xv. गुजरात 30% से 5%
xvi. गोवा 18% से 8%
xvii. कर्नाटक 28% से 18%

*****